



Daily करेंट अफेयर्स

»» 05 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. सरकार ने पुलों, सुरंगों और फ्लाईओवर वाले राजमार्गों पर टोल दरों में 50% तक की कटौती की है।



2 जुलाई, 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम (2008) में संशोधन किया, जिसके तहत राजमार्ग के उन हिस्सों पर टोल शुल्क में 50% तक की कमी की गई, जहां 50% से अधिक हिस्से में पुल, सुरंग, एलिवेटेड सड़कें या फ्लाईओवर हैं।

- पहले, ऐसे खंडों पर टोल की गणना संरचना की लंबाई के 10 गुना के हिसाब से की जाती थी, ताकि निर्माण की बढ़ी हुई लागत को संतुलित किया जा सके। नए नियम के तहत, टोल अब (संरचना की लंबाई का 10 गुना + सामान्य सड़क) या (खंड की कुल लंबाई का 5 गुना) में से जो भी कम हो, उसके आधार पर तय किए जाएंगे - जिससे कई शुल्कों में आधी कटौती हो जाएगी।

- उदाहरण के लिए, 40 किमी लंबे पूर्ण रूप से एलिवेटेड राजमार्ग पर पुराने टोल फार्मूले के अनुसार 400 किमी के बराबर टोल लिया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर 200 किमी के बराबर कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को 50% की बचत होगी।

Key Points:-

(i) यह सुधार विशेष रूप से उच्च बुनियादी ढांचे घनत्व वाले शहरी एक्सप्रेसवे को लाभान्वित करता है, जैसे कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर फ्लाईओवर-स्टडेड रिंग रोड और सुरंगें, जिससे निजी और वाणिज्यिक दोनों वाहनों के लिए लागत कम हो जाती है।

(ii) कम किए गए टोल सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू होंगे - चाहे वे फास्टैग-सक्षम हों या नहीं - और इससे लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय कमी आने, अंतर-शहर यात्रा को बढ़ावा मिलने और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

(iii) नीति अद्यतन को मंत्रालय द्वारा 2 जुलाई, 2025 को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया, जो वार्षिक फास्टैग पास (₹3,000/वर्ष) और दूरी-आधारित GNSS टोल जैसी आगामी पहलों के साथ-साथ इसके व्यापक टोल युक्तिकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. DAC ने 'भारतीय खरीदें-IDDM' योजना के तहत 1.05 लाख करोड़ रुपये की स्वदेशी रक्षा खरीद को मंजूरी दी।



3 जुलाई, 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 10 प्रमुख

रक्षा अधिग्रहण परियोजनाओं के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की, जो सभी खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी के अंतर्गत हैं।

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने देश में निर्मित महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए ₹44,000 करोड़ की लागत से 12 माइंस काउंटर-मेजर वेसल्स (MCMVs) और भारतीय सेना के लिए ₹30,000 करोड़ की लागत से क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM) सिस्टम शामिल हैं।

- अन्य स्वीकृतियां आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, और एक त्रि-सेवा एकीकृत सामान्य भंडारण प्रबंधन प्रणाली (Tri-Service Integrated Common Inventory Management System) से संबंधित हैं। इन रक्षा संपत्तियों का उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक क्षमता, गतिशीलता, युद्ध तैयारी और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य के अंतर्गत दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता को मजबूती देना है

- "भारतीय खरीदें-IDDM" नीति के तहत, सभी परियोजनाओं को भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया जाएगा, जिससे घरेलू रक्षा-औद्योगिक आधार को बढ़ावा मिलेगा। डीएसी का ध्यान रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) और निजी फर्मों के बीच तालमेल बढ़ाने पर है - जो मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है।

Key Points:-

(i) माइन काउंटर-मेजर वेसल्स (MCMV) की खरीद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नौसेना के पास दो दशकों से आधुनिक माइनस्वीपर्स की कमी है। विदेशी भागीदारों के सहयोग से भारतीय शिपयार्ड में बनाए गए इन जहाजों में गैर-चुंबकीय पतवार और उन्नत सोनार की सुविधा होगी, जिससे समुद्री सुरक्षा

बढ़ेगी।

(ii) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित QRSAM प्रणाली तीन रेजिमेंटों को स्वदेशी वायु-रक्षा क्षमता से लैस करेगी। प्रत्येक प्रणाली की रेंज लगभग 30 किमी है, जो स्तरित हवाई सुरक्षा में योगदान देती है और सेना की परिचालन तत्परता का समर्थन करती है।

(iii) अन्य स्वीकृत उपकरणों में मूर्ड माइंस, सुपर-रैपिड गन माउंट्स, पनडुब्बी स्वायत्त जहाज और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयां शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत की त्रि-सेवा युद्ध तैयारी, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन को मजबूत करना है।

3. पुरी ओडिशा का छठा नगर निगम बनेगा, जिससे शहरी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।



4 जुलाई, 2025 को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घोषणा की कि पुरी को नगर निगम में अपग्रेड किया जाएगा, जो राज्य का छठा नगर निगम होगा। इस कदम का उद्देश्य तीर्थयात्रियों, निवासियों और पर्यटकों के लिए बेहतर नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना है।

- पुरी सदर और ब्रह्मगिरी ब्लॉक की सात से आठ ग्राम पंचायतों को मौजूदा नगरपालिका क्षेत्र में मिलाकर पुरी नगर निगम की स्थापना की जाएगी।

इस विस्तारित अधिकार क्षेत्र से शहरी प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और सेवा वितरण में सुधार की उम्मीद है।

- इस उन्नयन के साथ, पुरी ओडिशा के अन्य नगर निगमों - भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, बरहामपुर और राउरकेला में शामिल हो गया है - जिससे शहर-स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने के लिए बड़े बजट आवंटन और अधिकार सुनिश्चित हो गए हैं।

- प्रशासनिक बदलाव का उद्देश्य बेहतर सड़कें, जल निकासी, स्ट्रीट लाइटिंग, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देना है, तथा रथ यात्रा और सुना बेशा जैसे त्योहारों के दौरान प्रतिवर्ष लाखों आगंतुकों की बढ़ती मांगों को पूरा करना है।

Key Points:-

(i) अधिकारियों ने बताया कि उन्नयन के लिए औपचारिक प्रक्रिया 5 जुलाई, 2025 को शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह शासन सुधार त्योहारों की भीड़, यातायात प्रवाह को प्रबंधित करने और मंदिर शहर में आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने में मदद करेगा।

(ii) नागरिक सुधारों के अलावा, सरकार ने आगामी परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें एक विश्व स्तरीय जगन्नाथ संग्रहालय, पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र शामिल है, जिसमें 300 सीटों वाला ऑडिटोरियम और दैनिक प्रकाश-और-ध्वनि शो होगा, ताकि पुरी की आध्यात्मिक-पर्यटन स्थल के रूप में भूमिका को मजबूत किया जा सके।

4. भारत ने मेरठ में अपना पहला WOA-मान्यता प्राप्त अश्व रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट स्थापित किया, जिससे वैश्विक अश्व व्यापार को बढ़ावा मिला।



3 जुलाई, 2025 को, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत भारत के रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स (आरवीसी) केंद्र और कॉलेज, मेरठ को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा देश के पहले अश्व रोग मुक्त कम्पार्टमेंट (EDFC) के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई।

- विश्व स्तर पर प्रमाणित EDFC प्रमुख अश्व रोगों को समाप्त करता है: अश्व संक्रामक एनीमिया, इन्फ्लूएंजा, पिरोग्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स और सुरा, जबकि भारत ने 2014 से अफ्रीकी अश्व रोग के लिए रोग मुक्त स्थिति बनाए रखी है, जो WOAH के सख्त जैव नियंत्रण मानकों को पूरा करता है।

- यह सुविधा उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में RVC सेंटर और कॉलेज में स्थित है, और WOAH स्थलीय पशु स्वास्थ्य कोड की आवश्यकताओं को पूरा करती है - मजबूत जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, पशु चिकित्सा निगरानी और निरंतर पशु स्वास्थ्य निगरानी प्रदान करती है।

- यह उपलब्धि भारतीय खेल घोड़ों और सवारों को बिना किसी संगरोध के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने और प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती है, जिससे वैश्विक घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में भारत की उपस्थिति बढ़ेगी और अश्व प्रजनन और उच्च मूल्य वाले व्यापार क्षेत्र को समर्थन मिलेगा।

Key Points:-

(i) इस पहल का नेतृत्व मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के RVC, भारतीय घुड़सवारी संघ (EFI) और यूपी पशुपालन विभाग के गठबंधन द्वारा किया गया था, और यह रोग की रोकथाम, स्वच्छता, कीट नियंत्रण और निगरानी के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत काम करता है।

(ii) यह उपलब्धि पशु स्वास्थ्य जैव सुरक्षा में भारत के नेतृत्व को दर्शाती है, जो पोल्ट्री में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (HPAI) मुक्त कम्पार्टमेंट स्थापित करने और अपने वैश्विक निर्यात-तैयार कृषि पोर्टफोलियो को बढ़ाने के अपने व्यापक उद्देश्य के साथ संरेखित है।

5. केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हाई-स्पीड राउटर 'SAKSHAM-3000' लॉन्च किया।



3 जुलाई, 2025 को केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (MoS) डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने SAKSHAM-3000 लॉन्च किया, जो 25.6 टेराबिट प्रति सेकंड (Tbps) की थ्रूपुट के साथ अत्याधुनिक उच्च क्षमता वाला राउटर है। इस राउटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) द्वारा विकसित किया गया था और इसका उद्घाटन संचार

मंत्रालय (MoC), दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत नई दिल्ली में इसके परिसर में किया गया था।

- SAKSHAM-3000 एक उन्नत राउटर है जिसे बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग क्लस्टर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और AI वर्कलोड के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 5G और 6G नेटवर्क सहित अगली पीढ़ी की डिजिटल ज़रूरतों के लिए तैयार किया गया है। राउटर बड़े डेटा, एज कंप्यूटिंग और राष्ट्रीय नेटवर्क जैसे अत्याधुनिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त प्रदर्शन के साथ भारत की डेटा सेंटर क्षमता को बढ़ाता है।

- राउटर 400 गीगाबिट (G) के 32 पोर्ट और 1G से 400G तक की ईथरनेट स्पीड को सपोर्ट करता है। यह बहुमुखी प्रतिभा मौजूदा और भविष्य की दोनों प्रणालियों के साथ संगतता को सक्षम बनाती है, जो भारत की बढ़ती डेटा मांगों के लिए एक लचीली लेकिन शक्तिशाली रीढ़ प्रदान करती है और मजबूत क्लाउड-आधारित और ऑन-प्रीमाइसेस बुनियादी ढांचे का समर्थन करती है।

- यह लेयर-2, आईपी और एमपीएलएस प्रोटोकॉल के साथ लीगेसी और क्लाउड-नेटिव नेटवर्क का समर्थन करता है। SAKSHAM-3000 में मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (MPLS), समय-संवेदनशील अनुप्रयोगों के लिए पॉइंट-टू-पॉइंट प्रोटोकॉल (PTP) और सटीक और कुशल सिग्नल डिलीवरी के लिए सिंक्रोनस ईथरनेट (Sync-E) जैसी सुविधाएँ शामिल हैं, जो उच्च उपलब्धता और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करती हैं।

Key Points:-

(i) SAKSHAM-3000 राउटर में अत्यंत कम विलंबता, उच्च गति डेटा प्रोसेसिंग की सुविधा है, तथा यह C-DOT के स्वामित्व वाले राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम (CROS) द्वारा संचालित है।

(ii) इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर लचीलेपन और मापनीयता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो

CLOS (क्लोज नेटवर्क) टोपोलॉजी की सभी परतों में सहज एकीकरण को सक्षम बनाता है - लीफ नोड्स से लेकर स्पाइन नोड्स तक। यह डिज़ाइन रूटिंग दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, सिग्नल की भीड़ को कम करता है, और बड़े डेटा सेंटर और टेलीकॉम नेटवर्क जैसे उच्च घनत्व वाले डेटा वातावरण में मजबूत प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

(iii) SAKSHAM-3000 डिजिटल विनिर्माण में भारत के 'डिजिटल इंडिया' मिशन और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करता है। इस राउटर का स्वदेशी विकास महत्वपूर्ण दूरसंचार हार्डवेयर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है और सुरक्षित और स्केलेबल नेटवर्किंग तकनीक के साथ वैश्विक डिजिटल हब बनने के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

6. MiPhi एंटरप्राइज़ SSDs डिज़ाइन और निर्माण करने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई।



जून 2025 में, माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक्स (भारत) और फिसन टेक्नोलॉजी (ताइवान) के बीच एक संयुक्त उद्यम, मिफी सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्थानीय स्तर पर एंटरप्राइज़-ग्रेड सॉलिड स्टेट ड्राइव (SSDs) डिज़ाइन और निर्माण करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनकर इतिहास रच देगी।

• यह घोषणा नई दिल्ली में की गई, जो भारत के सेमीकंडक्टर और डेटा भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़ी प्रगति है।

• यह उपलब्धि भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन देती है, विशेष रूप से अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीकों और डेटा स्टोरेज समाधान में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए।

• MiPhi द्वारा बनाए गए एंटरप्राइज़ SSDs विशेष रूप से डेटा सेंटर्स, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और एज कंप्यूटिंग जैसे उपयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये SSDs बेहद तेज गति, उच्च टिकाऊपन और एंटरप्राइज़-ग्रेड सुरक्षा प्रदान करते हैं।

Key Points:-

(i) 2025 तक वैश्विक डेटा उत्पादन के 180 ज़ेटाबाइट्स (ZB) से अधिक होने का अनुमान है। ऐसे में, भारत में बने ये SSDs देश की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करेंगे और घरेलू तकनीकी बुनियादी ढांचे को और आत्मनिर्भर बनाएंगे।

(ii) वैश्विक एंटरप्राइज़ SSD बाजार के 2024 में 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2028 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जिससे भारत को वैश्विक वैल्यू चेन में मजबूत स्थान मिलने की उम्मीद है।

(iii) इसके साथ ही भारत की डेटा सेंटर क्षमता भी तेज़ी से बढ़ रही है और 2026 तक इसके 1.3 गीगावॉट (GW) को पार करने की संभावना है, जिसे 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश का समर्थन प्राप्त है। इससे स्वदेशी SSDs की मांग और बढ़ेगी।

7. SMPP को 27,700 बुलेटप्रूफ जैकेट और 11,700 उन्नत हेलमेट के लिए भारतीय सेना से 300 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला।

SMPP

PROTECTING THOSE WHO PROTECT US

भारत की अग्रणी रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी SMPP प्राइवेट लिमिटेड को आपातकालीन खरीद प्रक्रिया-5 (EP-5) के तहत भारतीय सेना से ₹300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस अनुबंध में 27,700 अत्याधुनिक बुलेटप्रूफ जैकेट (BPJs) और 11,700 उन्नत लड़ाकू हेलमेट की आपूर्ति शामिल है। यह ऑर्डर आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी विनिर्माण के माध्यम से सैन्य सुरक्षा बढ़ाने के भारत के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।

- SMPP द्वारा आपूर्ति किये गये बुलेटप्रूफ जैकेट राष्ट्रीय न्याय संस्थान (NIJ) के मानकों के अनुसार स्तर III और IV के हैं, जो 7.62×39 मिमी और 7.62×51 मिमी हार्ड-कोर गोला-बारूद को झेलने में सक्षम हैं।

- ये जैकेट मॉड्यूलर, हल्के होते हैं, तथा इनमें गतिशील भार वितरण, त्वरित-रिलीज़ प्रणाली और सांस लेने योग्य जलरोधी कपड़े जैसी विशेषताएं होती हैं, जो युद्ध क्षेत्रों में आराम और उत्तरजीविता को बढ़ाती हैं।

- ऑर्डर में शामिल उन्नत हेलमेट मालिकाना मिश्रित सामग्री का उपयोग करके डिज़ाइन किए गए हैं और AK-47 हार्ड स्टील कोर बुलेट के खिलाफ भी सुरक्षा

प्रदान करते हैं। ये बैलिस्टिक हेलमेट RIA लेवल IIIA मानकों (रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मेड) को पूरा करते हैं, और नाइट विजन डिवाइस (NVDs), एकीकृत संचार समर्थन के लिए माउंट से लैस हैं, और विस्तारित लड़ाकू मिशनों के लिए बेहतर कवरेज और आराम प्रदान करते हैं।

Key Points:-

(i) हरियाणा के पलवल में SMPP की विनिर्माण सुविधा, साथ ही नई दिल्ली में इसका R&D बेस, भारत के व्यक्तिगत सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ii) कवच प्रौद्योगिकी में 17 से अधिक दायर और 10 स्वीकृत पेटेंट रखने वाली SMPP, व्यक्तिगत शारीरिक कवच के लिए भारतीय बाजार के 90% से अधिक हिस्से पर हावी है और रक्षा मंत्रालय (MoD) के तहत 2018 से 230,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को सुरक्षात्मक गियर की आपूर्ति कर चुकी है।

8. नीति आयोग ने रासायनिक उद्योग मूल्य शृंखलाओं में भारत की वैश्विक भूमिका को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रिपोर्ट लॉन्च की।



3 जुलाई, 2025 को नीति आयोग ने नई दिल्ली में “रासायनिक उद्योग: वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs) में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना” शीर्षक से

एक रणनीतिक रिपोर्ट लॉन्च की। इस रिपोर्ट का उद्देश्य 2040 तक भारत को रासायनिक क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।

- इस रिपोर्ट का अनावरण नीति आयोग के CEO BVR सुब्रह्मण्यम ने किया। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में शिक्षा जगत, उद्योग जगत और सरकार के हितधारकों ने इस क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों और व्यापार विस्तार पर चर्चा की।

- रासायनिक उत्पादन के मामले में भारत विश्व स्तर पर 6वें और एशिया में तीसरे स्थान पर है, जो भारत के विनिर्माण GVA में 7% का योगदान देता है। हालाँकि, यह वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) के केवल 3.5% में भाग लेता है और 2023 में 31 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया है। रिपोर्ट में इसे भारत के लिए पाटने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर अंतर के रूप में पहचाना गया है।

- भारत का घरेलू रासायनिक बाज़ार, जो 2023 में 220 बिलियन अमरीकी डॉलर का है, 2030 तक 400-450 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने और 2040 तक 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर को पार करने का अनुमान है, जो कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग से प्रेरित है। उचित नीतिगत हस्तक्षेप के साथ, भारत 2040 तक अपने जीवीसी हिस्से को 12% तक बढ़ा सकता है।

Key Points:-

(i) यह रिपोर्ट प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करती है, जैसे कि कच्चे माल (फीडस्टॉक) और विशेष रासायनिक उत्पादों (स्पेशलिटी केमिकल्स) पर उच्च आयात निर्भरता, अनुसंधान एवं विकास (R&D) में

कम निवेश (भारत रासायनिक GDP का केवल 0.7% निवेश करता है, जबकि वैश्विक औसत 2.3% है), अपर्याप्त आधारभूत संरचना, उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, पर्यावरण स्वीकृतियों में देरी (12 से 18 महीने), और उन्नत रासायनिक तकनीकों में 30% कौशल की कमी।

(ii) प्रमुख सिफारिशों में बंदरगाहों के पास रसायन विनिर्माण केन्द्रों की स्थापना (जैसे दहेज, पारादीप और विजाग), पर्यावरणीय मंजूरी को सुव्यवस्थित करना, फीडस्टॉक्स पर आयात शुल्क कम करना, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहनों में वृद्धि करना, उद्योग-अकादमिक सहयोग मंचों की स्थापना करना और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रसायनों को मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में शामिल करना शामिल है।

(iii) रिपोर्ट में उच्च मूल्य वाले उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI), ITIs और पॉलिटेक्निक के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल ढांचा विकसित करने और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए FDI आकर्षित करने का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य 7 लाख से अधिक कुशल नौकरियां पैदा करना, 2030 तक भारत के रासायनिक निर्यात को दोगुना करके 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना और 2040 तक व्यापार घाटे को खत्म करना है।

INTERNATIONAL

1. विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 30 जून से 3 जुलाई, 2025 तक सेविले, स्पेन में आयोजित किया जाएगा।



विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FfD4) 30 जून से 3 जुलाई, 2025 तक स्पेन के सेविले में आयोजित किया गया। 4 दिवसीय उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में 50 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों सहित 15,000 से अधिक प्रतिभागियों ने वैश्विक वित्त और सतत विकास के प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

- यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA) द्वारा हर दस साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, यूएसए में है। FfD4 ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का समर्थन करने के लिए एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।

- भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय (MoF) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MoCA), भारत सरकार ने किया। उन्होंने FfD4 शिखर सम्मेलन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- FfD4 का एक प्रमुख आकर्षण "रेसिलिएंट रेमिट" पहल का शुभारंभ था, जिसके लिए 4.26 मिलियन यूरो का निधि आवंटन किया गया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय धन-हस्तांतरण की लागत को कम करना और प्रवासी परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना था।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम में आठ देशों - फ्रांस, केन्या, बारबाडोस, स्पेन, सोमालिया, बेनिन, सिएरा लियोन और एंटीगुआ और बारबुडा - द्वारा "विमानन एकजुटता गठबंधन" का गठन भी किया गया, जिसका उद्देश्य प्रीमियम और बिजनेस श्रेणी की हवाई यात्रा पर एकजुटता कर के माध्यम से जलवायु वित्त जुटाना है।

(ii) FfD4 का समापन 3 जुलाई, 2025 को सेविला भागीदारी समझौते (SPA) के तहत 130 अंतर्राष्ट्रीय पहलों के शुभारंभ के साथ हुआ, जिससे विकासशील देशों में कर सुधारों और सार्वजनिक-निजी निवेशों को मजबूत करने के लिए सेविला प्रतिबद्धता या कॉम्प्रोमिसो डी सेविला का कार्यान्वयन शुरू हुआ।

2. इजराइल और अमेरिका के साथ संघर्ष के बीच ईरान ने IAEA सहयोग निलंबित कर दिया।



2 जुलाई, 2025 को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ ईरान के सहयोग को रोकने वाला कानून पारित किया। यह निर्णय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ईरानी परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हवाई हमलों से जुड़े 12-दिवसीय संघर्ष के बाद आया।

● ईरान की संसद ने विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया - 221 मत इसके पक्ष में थे, तथा केवल एक सदस्य अनुपस्थित था - तथा इसे गार्जियन काउंसिल और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से त्वरित अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसके तहत यह अनिवार्य कर दिया गया कि भविष्य में IAEA के सभी निरीक्षणों को राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा।

● हालाँकि परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के तहत सहयोग को निलंबित कर दिया गया है, ईरान ने पुष्टि की है कि वह संधि से पीछे नहीं हट रहा है। उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह ईरान की परमाणु सुविधाओं और कर्मियों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक सशर्त उपाय है।

Key Points:-

(i) इजरायल ने यूरोपीय संघ के E3 (जर्मनी, फ्रांस, UK) से 2015 के परमाणु समझौते के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का आग्रह किया। अमेरिका ने इस कदम को "अस्वीकार्य" बताया और ईरान पर परमाणु पारदर्शिता कम करने का आरोप लगाया। यूरोपीय राजनयिकों को डर है कि ईरान की हिम्मत बढ़ गई है और वह गुप्त परमाणु अभियान चला सकता है।

(ii) निलंबन के बाद, IAEA की टीम ईरान से वापस जाने लगी, मुख्य रूप से आर्मेनिया और वियना के लिए भूमि मार्गों के माध्यम से, जिससे परमाणु अस्पष्टता का माहौल पैदा हो गया। इस बीच, ईरान ने कहा कि सुरक्षा गारंटी मिलने के बाद निरीक्षण फिर से शुरू हो सकता है।

3. यूरोपीय आयोग ने संशोधित यूरोपीय संघ जलवायु कानून के तहत 2040 तक 90% शुद्ध GHG उत्सर्जन में कटौती का प्रस्ताव रखा।



2 जुलाई 2025 को, यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ जलवायु कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें 1990 के स्तर की तुलना में 2040 तक शुद्ध ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में 90% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया, साथ ही इसमें लचीलेपन के अंतर्निहित उपाय भी शामिल किए गए।

● नए प्रस्ताव में 2040 के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी 90% शुद्ध जीएचजी कटौती लक्ष्य को शामिल किया गया है, जो 2030 तक वर्तमान 55% कटौती और 2050 जलवायु तटस्थता लक्ष्य पर आधारित है। फिटफॉर90 नामक यूरोपीय संघ जलवायु कानून में संशोधन यूरोपीय ग्रीन डील के साथ संरेखित है, जो दीर्घकालिक पूर्वानुमान और निवेशक विश्वास प्रदान करता है।

● राजनीतिक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए, योजना में लचीले तंत्र शामिल हैं: 2036 से उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट का उपयोग करके उत्सर्जन लक्ष्य के 3% तक की पूर्ति की अनुमति देना, घरेलू कार्बन निष्कासन (जैसे कार्बन कैप्चर और भंडारण) की अनुमति देना, और विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को सक्षम बनाना - लागत प्रभावी, न्यायसंगत संक्रमण के लिए प्रमुख उपकरण।

Key Points:-

(i) योजना में व्यावहारिकता जर्मनी, पोलैंड और हंगरी जैसे सदस्य देशों के साथ राजनीतिक समझौतों को

दर्शाती है। लेकिन पर्यावरण समूहों ने चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑफसेट यूरोपीय संघ के आंतरिक डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं। जलवायु आयुक्त वोपके होकेस्ट्रा ने जोर देकर कहा कि कड़े मानक मजबूती बनाए रखेंगे।

(ii) नवंबर में संयुक्त राष्ट्र COP30 शिखर सम्मेलन से पहले 2026 में इस कानून को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। 85% सार्वजनिक समर्थन से समर्थित यह लक्ष्य वैश्विक जलवायु संवादों का नेतृत्व करने और स्वच्छ निवेश को बढ़ावा देने की यूरोप की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है - साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है।

(iii) हाल ही में, यूरोपीय संघ ने "प्रकृति ऋण" के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जिसका उद्देश्य किसानों और वन प्रबंधकों को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है - जैसे कि पुनर्वनीकरण, आर्द्रभूमि पुनर्वास और टिकाऊ भूमि उपयोग। यह पहल कंपनियों और सरकारों को कार्बन ऑफसेट के समान लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर केंद्रित सत्यापित क्रेडिट खरीदने में सक्षम बनाकर जैव विविधता संरक्षण में €37 बिलियन वार्षिक फंडिंग अंतर को भरने का प्रयास करती है। एक विशेषज्ञ समूह से 2027 तक पायलट रोलआउट के साथ मजबूत मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं को डिजाइन करने की उम्मीद है।

BANKING & FINANCE

1. RBI ने जून 2025 में साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए सभी बैंकों को दूरसंचार विभाग (DoT) की वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया



30 जून, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और सहकारी बैंकों को दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा विकसित वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) को अपनाने का निर्देश जारी किया।

• दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) द्वारा मई 2025 में लॉन्च किया गया वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI), राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP), दूरसंचार विभाग के चक्षु प्लेटफॉर्म और बैंकों और दूरसंचार प्रदाताओं से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के रूप में मूल्यांकन करता है।

• यह सिस्टम वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए DoT के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) के साथ API-आधारित एकीकरण का उपयोग करता है। बैंक अब संदिग्ध लेनदेन को रोक सकते हैं, उच्च जोखिम वाले भुगतानों में देरी कर सकते हैं और ग्राहकों को अलर्ट भेज सकते हैं, जिससे संभावित धोखाधड़ी पर तुरंत लगाम लग सकती है।

• फोनपे, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पेटीएम और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सहित प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही FRI को एकीकृत कर लिया है, जो एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)

पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने में उपकरण की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।

Key Points:-

- (i) RBI का निर्देश RBI और DoT के बीच अंतर-एजेंसी सहयोग की ताकत को रेखांकित करता है। यह कदम डिजिटल इंडिया विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए डिजिटल विश्वास बनाने की भारत की रणनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है और साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ भारत की सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।
- (ii) यह निर्देश विभिन्न संस्थानों को कवर करता है: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, सहकारी बैंक और NBFCs, जो भारत की संपूर्ण डिजिटल वित्त मूल्य श्रृंखला में वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने की क्षमता को प्रभावी ढंग से बढ़ाते हैं।
- (iii) दूरसंचार विभाग का DIU एक मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची (MNRL) भी रखता है, जिसमें साइबर अपराध लिंक या सिम के दुरुपयोग के लिए चिह्नित नंबर शामिल होते हैं। FRI एक जीवंत प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे भारत के डिजिटल सुरक्षा जनादेशों के अनुपालन को बनाए रखते हुए लगातार विकसित हो रही धोखाधड़ी की रणनीति के अनुकूल होने के लिए अपडेट किया जाता है।

2. GCF ने उभरती स्वच्छ ऊर्जा में तेजी लाने के लिए ADB की भारत ग्रीन फाइनेंस सुविधा के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी।



1 जुलाई, 2025 को ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) ने एशियाई विकास बैंक (ADB) की भारत ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी (IGFF) को समर्थन देने के लिए रियायती वित्तपोषण में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी, जिससे भारत के उभरते स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश संभव हो सकेगा।

- ADB के नेतृत्व में और GCF द्वारा समर्थित IGFF का उद्देश्य विकास वित्त संस्थानों (DFIs) को ऋण की लाइनें प्रदान करके सार्वजनिक और निजी पूंजी को आकर्षित करना है। फोकस क्षेत्रों में चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, संपीड़ित बायोगैस, इलेक्ट्रिक परिवहन और विकेन्द्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं।

- एक महत्वपूर्ण विशेषता USD65 मिलियन जोखिम-साझाकरण सुविधा है, जो आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करती है। यह सुविधा छोटे और हरित स्टार्ट-अप को किफायती वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद करती है - विशेष रूप से संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं में - उच्च ऋणदाता जोखिम से बचने की चुनौती पर काबू पाने में।

- IGFF भारत में GCF के साथ ADB का पहला जलवायु वित्त सहयोग है। ADB के ऊर्जा परिवर्तन निदेशक प्रदीप थरकन ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए भारत के मार्ग का समर्थन करता है, जबकि कठिन क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करता है।

Key Points:-

(i) यह कार्यक्रम उभरती प्रौद्योगिकियों को वित्तपोषित करने के लिए भारत भर में DFIs की क्षमता को बढ़ाता है। यह स्केलेबल ग्रीन फाइनेंस के लिए एक खाका पेश करता है, भारत को स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है और जलवायु-संरेखित निवेश के लिए संस्थागत तत्परता को प्रोत्साहित करता है।

(ii) IGFF का ध्यान उद्योग, कृषि और ग्रामीण परिवहन जैसे क्षेत्रों पर है, जो कार्बन-गहन क्षेत्रों को संबोधित करते हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा पर कम निर्भर हैं। यह सतत विकास मॉडल की ओर बदलाव को बढ़ाता है, समान ऊर्जा पहुंच और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देता है।

(iii) एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए GCF के निदेशक हेमंत मंडल ने इस पहल की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यह एक "अभिनव, उच्च प्रभाव वाला जलवायु समाधान" है, जो क्षेत्र में सतत विकास और जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देता है, तथा GCF के मिशन को मजबूत करता है।

3. SBI ने वित्त वर्ष 2025 में विश्व अर्थव्यवस्था में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़े और वैश्विक GDP वृद्धि में 1.1% का योगदान दिया।



SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट से पता चला है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत ने वैश्विक GDP वृद्धि में 297 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया - लगभग 6.7%। उल्लेखनीय रूप से, अकेले भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, जो कुल वैश्विक वृद्धि का 1.1% है।

● वित्त वर्ष 2025 में वैश्विक GDP वृद्धि में SBI का योगदान 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कई छोटे देशों के आर्थिक उत्पादन से भी अधिक है। यह राशि उसी वर्ष भारत की घरेलू GDP वृद्धि का 16% भी है, जो राष्ट्रीय आर्थिक गतिशीलता में SBI की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

Key Points:-

(i) वित्त वर्ष 2025 के दौरान, वित्तीय सेवा क्षेत्र में SBI का सकल मूल्य वर्धन (GVA) ₹132,157 करोड़ से बढ़कर ₹138,533 करोड़ हो गया, जो साल-दर-साल 5% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। यह GVA अकेले भारत में कुल वित्तीय क्षेत्र मूल्य वर्धन का 8.7% दर्शाता है।

(ii) SBI की बैलेंस शीट अब 0.77 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (₹66 ट्रिलियन) से अधिक है - जो लगभग 175 देशों के सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक है। इसने लगातार तीसरे वर्ष ₹70,901 करोड़ का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ दर्ज करते हुए भारत की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी।

(iii) SBI लगभग 52 करोड़ ग्राहक खातों को संसाधित करता है, PMJDY, PMSBY और APY जैसी पहलों का समर्थन करता है, और इसका योनो ऐप 8.8 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं का दावा करता है, जो भारत की डिजिटल बैंकिंग क्रांति की रीढ़ के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करता है।

ECONOMY & BUSINESS

1. NSE जुलाई 2025 डेटा: गुजरात महाराष्ट्र और यूपी के बाद 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया।



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 में गुजरात 1 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों की उपलब्धि को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया। यह उपलब्धि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद है, जो भारत के इक्विटी बाजार परिदृश्य में गुजरात की बढ़ती भागीदारी को उजागर करती है।

- NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) के आंकड़ों से पता चला है कि मई 2025 तक भारत में लगभग 11.5 करोड़ पंजीकृत निवेशक थे, जिनमें से अकेले मई में 11 लाख से ज्यादा नए निवेशक जुड़े। यह महीने-दर-महीने (MoM) निवेशकों की 9% की मज़बूत वृद्धि को दर्शाता है, जो भारत के खुदरा निवेश की गति को दर्शाता है।

- क्षेत्रीय दृष्टि से, उत्तर भारत 4.2 करोड़ निवेशकों के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद पश्चिम भारत (3.5 करोड़), दक्षिण भारत (2.4 करोड़) और पूर्वी भारत (1.4 करोड़) का स्थान रहा। 1 करोड़ निवेशकों वाले क्लब में गुजरात के शामिल होने से राष्ट्रीय निवेशक आधार में पश्चिम भारत का योगदान काफी बढ़ गया।

- चारों क्षेत्रों में से, उत्तर भारत और पूर्वी भारत ने 2024 की तुलना में सबसे अधिक वार्षिक निवेशक वृद्धि दर्ज की, जिसमें क्रमशः 24% और 23% की वृद्धि हुई। दक्षिण भारत ने 22% और पश्चिम भारत ने इसी अवधि में 17% की वृद्धि दिखाई।

Key Points:-

(i) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात का संचयी योगदान अब भारत के कुल स्टॉक निवेशक आधार का 36% है, जो इन राज्यों में वित्तीय परिपक्वता और डिजिटल पहुंच को दर्शाता है।

(ii) NSE के आंकड़ों ने भी दीर्घकालिक रुझान को बनाए रखने का संकेत दिया। भारत ने अगस्त 2024 में 9 करोड़ निवेशकों का आंकड़ा पार कर लिया और सिर्फ 10 महीनों में 2.5 करोड़ और निवेशक जोड़े, जो डिजिटल ऑनबोर्डिंग और निवेश जागरूकता पहलों में वृद्धि के कारण हुआ।

(iii) गुजरात में फरवरी से मई 2025 तक लगातार वृद्धि देखी गई, जिसमें प्रति माह औसतन 10.8 लाख नए निवेशक जुड़े, जबकि राष्ट्रीय औसत 19.3 लाख था। यह राज्य में तेजी से वित्तीय समावेशन और शेयर बाजार साक्षरता वृद्धि को दर्शाता है।

2. माइक्रोसॉफ्ट ने 25 वर्षों के बाद पाकिस्तान में परिचालन बंद कर दिया है और पुनर्गठन के तहत केवल संपर्क-मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया।



4 जुलाई, 2025 को, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने पाकिस्तान में अपने परिचालन कार्यालय को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया, जबकि यह देश में ढाई दशक से अधिक समय तक मौजूद रहा। यह निर्णय माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक पुनर्गठन योजना का हिस्सा है, जिसमें महत्वपूर्ण नौकरियों में कटौती, रणनीतिक बदलाव और उभरते बाजारों में भागीदार-नेतृत्व वाले संचालन की ओर पुनर्गठन शामिल है।

- माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में पाकिस्तानी बाजार में प्रवेश किया, जिसका उद्देश्य लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर तक पहुंच का विस्तार करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और उद्यम-स्तर की सेवाएं प्रदान करना था। पिछले कुछ वर्षों में, इसने पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग (HEC) के साथ कार्यक्रम आयोजित किए, छात्रों के लिए माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप प्रतियोगिताएं शुरू कीं और स्मार्ट क्लासरूम और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं पर सहयोग किया।

- स्थानीय कार्यालय बंद होने के बावजूद, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में साझेदार कंपनियों और क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से अपनी सेवाएं देना जारी रखेगा। साझेदार-नेतृत्व वाले मॉडल में यह बदलाव लागत-दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है, जबकि बाजार तक पहुंच और ग्राहक सेवा क्षमता को बनाए रखा गया है।

- यह निर्णय माइक्रोसॉफ्ट की व्यापक वैश्विक पुनर्गठन रणनीति के अनुरूप है जिसके तहत कंपनी लगभग 9,000 नौकरियों को समाप्त कर रही है, जो इसके वैश्विक कार्यबल का लगभग 4% है। कंपनी ने खुलासा किया कि उसने 950 मिलियन अमरीकी डॉलर का पुनर्गठन-संबंधित वित्तीय प्रभार लिया है, जिसमें 200 मिलियन अमरीकी डॉलर का विच्छेद और लाभ शामिल है।

Key Points:-

(i) माइक्रोसॉफ्ट का पूर्ण परिचालन से बाहर निकलना ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान गंभीर व्यापक आर्थिक तनाव का सामना कर रहा है। देश ने वित्त वर्ष 24 में 24.4 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया, बढ़ती मुद्रास्फीति, आईटी सेवाओं पर भारी कराधान, मुद्रा अवमूल्यन और असंगत नियामक ढांचे, इन सभी ने वैश्विक तकनीकी फर्मों के लिए बाजार संचालन को जोखिम भरा बना दिया है।

(ii) माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के संस्थापक कंटी मैनेजर जवाद रहमान ने बंद होने को "कॉर्पोरेट निकास से कहीं अधिक" बताया, इसे निवेशकों के बिगड़ते विश्वास का संकेत बताया। उद्योग पर नजर रखने वाले इसे पाकिस्तान के आईटी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक चेतावनी और तकनीकी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में संभावित बाधा के रूप में देखते हैं।

(iii) जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार कम कर दिया है, भारत जैसे पड़ोसी देशों में वैश्विक तकनीकी परिचालन का विस्तार हो रहा है। इसमें अरबों डॉलर के डेटा सेंटर, AI रिसर्च हब और गूगल, एप्पल और अमेज़ॉन जैसी कंपनियों द्वारा सेमीकंडक्टर निवेश शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान का तकनीकी क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए तुलनात्मक रूप से कम आकर्षक बन गया है।

MOUs and Agreement

1. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पनडुब्बी ट्रैकिंग पर संयुक्त अनुसंधान के लिए तीन वर्षीय समुद्री निगरानी समझौते पर हस्ताक्षर किए।



भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 3 जुलाई, 2025 को भारत की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला (NPOL) और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूह (DSTGs) के बीच शुरू की गई तीन वर्षीय संयुक्त अनुसंधान परियोजना के माध्यम से समुद्र के नीचे निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। यह समझौता पनडुब्बियों और स्वायत्त पानी के नीचे वाहनों (AUVs) पर नज़र रखने की क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है।

- इस द्विपक्षीय परियोजना को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा कोच्चि, केरल में NPOL और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग के अंतर्गत DSTG के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य ज्ञान साझा करना, संयुक्त समुद्री परीक्षण और वास्तविक समय में पनडुब्बी का पता लगाने के लिए तकनीकी सह-विकास को बढ़ावा देना है।

- परियोजना के तहत सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र टोड एरे टारगेट मोशन एनालिसिस (TMA) है, जो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पनडुब्बियों या AUV द्वारा उत्सर्जित पानी के नीचे ध्वनिक संकेतों को पकड़ने

के लिए हाइड्रोफोन से लैस लंबी केबल शामिल हैं। इन संकेतों को दिशा, गति और स्थान ट्रैकिंग के लिए संसाधित किया जाता है।

- यह परियोजना TMA एल्गोरिदम विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है जो सक्रिय सोनार के बिना पानी के नीचे के खतरों की निष्क्रिय ट्रैकिंग की अनुमति देता है, जिससे सैन्य अभियानों में चुपके से लाभ मिलता है। इन एल्गोरिदम का परीक्षण भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई दोनों जलक्षेत्रों में किया जाएगा, इससे पहले कि उन्हें लाइव ऑपरेशन के लिए तैनात किया जाए।

Key Points:-

(i) एक अन्य महत्वपूर्ण शोध घटक शोर प्रबंधन है, जिसका उद्देश्य समुद्री वातावरण के कारण होने वाले शोर विरूपण को कम करना है, जिससे ध्वनिक संकेत पहचान की सटीकता में सुधार होगा। TMA और परिष्कृत शोर कम करने वाले एल्गोरिदम का संयोजन पानी के नीचे की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा।

(ii) यह भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग बढ़ते हिंद-प्रशांत सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है और रक्षा अनुसंधान में भारत की आत्मनिर्भर भारत रणनीति के अनुरूप है।

(iii) NPOL एक प्रमुख DRDO प्रयोगशाला है जिसके निदेशक डॉ. दुव्वुरी शेषगिरी हैं और यह कोच्चि, केरल में स्थित है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. साहिल किनी को फिनटेक इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO नियुक्त किया गया।



फिनटेक स्टार्टअप सेतु के सह-संस्थापक और इंडियास्टैक आर्किटेक्चर के अग्रणी साहिल किनी को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH), बेंगलुरु का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है, जो संस्थापक CEO राजेश बंसल का स्थान लेंगे।

- साहिल किनी को छह महीने तक चले भर्ती अभियान के बाद चुना गया, जिसमें 400 से ज़्यादा आवेदक शामिल हुए, जिनमें फिनटेक लीडर, बैंक अधिकारी और विनियामक विशेषज्ञ शामिल थे। उनकी नियुक्ति - RBIH बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई - इस नेतृत्व की भूमिका की उच्च-प्रोफ़ाइल प्रकृति को दर्शाती है।

- IIT मद्रास के पूर्व छात्र, Kini ने 2022 में पाइन लैब्स द्वारा अधिग्रहण से पहले API-आधारित वित्तीय बुनियादी ढांचे में सेतु को प्रमुखता दिलाई, और इंडियास्टैक परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई - जिसमें आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) शामिल हैं - राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान ढांचे को मजबूत करते हैं।

Key Points:-

(i) मार्च 2022 में लॉन्च किए गए RBIH का मिशन फिनटेक स्टार्टअप, बैंकों, विनियामकों और शिक्षाविदों को जोड़कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। संस्थापक सीईओ राजेश बंसल के

नेतृत्व में, हब ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए फ्रिक्शनलेस क्रेडिट और स्वानारी™ प्लेटफ़ॉर्म जैसे उच्च-प्रभाव वाले समाधान पेश किए, जिन्हें G20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया।

(ii) CEO के रूप में, किनी को RBIH को साझेदारी का विस्तार करने, नए उत्पादों का परीक्षण करने और समावेशी ऋण, धोखाधड़ी का पता लगाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में कार्रवाई योग्य अनुसंधान करने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। उनका कार्य उपभोक्ता संरक्षण और सार्वजनिक जुड़ाव को भविष्य के लिए तैयार फिनटेक समाधानों के लिए प्रेरित करने के साथ संतुलित करना है।

2. सब-लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट प्रशिक्षु बनीं।



उत्तर प्रदेश के मेरठ की सब-लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को INS डेगा, विशाखापत्तनम में दूसरे बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स से 'विंग्स ऑफ गोल्ड' के साथ स्नातक होने के बाद भारतीय नौसेना के विशिष्ट लड़ाकू स्ट्रीम में शामिल किया गया है, यह पहली बार है जब किसी महिला ने नौसेना सेवा में लड़ाकू विमानन में प्रवेश किया है।

- 3 जुलाई, 2025 को, सब-लेफ्टिनेंट पूनिया ने नौसेना स्टाफ (वायु) के सहायक प्रमुख रियर

एडमिरल जनक बेवली से प्रतिष्ठित विंग्स ऑफ गोल्ड प्राप्त किया, जिससे वह हॉक 132 जेट ट्रेनर पर उन्नत प्रशिक्षण पूरा करके आधिकारिक तौर पर नौसेना विमानन के लड़ाकू पायलट स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई।

● आस्था पूनिया, जो 20 की उम्र के आसपास की हैं, मेरठ की रहने वाली हैं और उनके पास बी.टेक की डिग्री है। उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के ज़रिए नौसेना में प्रवेश किया, भारतीय नौसेना अकादमी (एडिमाला) और वायु सेना अकादमी (डुंडीगल) में प्रशिक्षण लिया, उसके बाद विशाखापत्तनम में हॉक जेट प्रशिक्षण के लिए गईं।

Key Points:-

(i) आस्था पूनिया एक वर्ष के लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगी, जिसमें उन्हें आईएनएस विक्रान्त और INS विक्रमादित्य के डेक से मिग-29के और संभावित भविष्य के राफेल-एम जैसे अग्रणी नौसैनिक जेट उड़ाने के लिए तैयार किया जाएगा।

(ii) यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय नौसेना की लड़ाकू भूमिकाओं में लैंगिक समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और नारी शक्ति (महिला शक्ति) के लोकाचार को बढ़ावा देती है। यह भारतीय वायु सेना में इसी तरह की प्रगति को दर्शाता है, जिसने 2016 में महिलाओं के लिए लड़ाकू स्ट्रीम खोली थी।

AWARDS

1. WHO SEAR निदेशक साइमा वाजेद को बैंकॉक, थाईलैंड में 24वें IMHC में मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।



1 जुलाई, 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन - दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र (WHO SEAR) की क्षेत्रीय निदेशक, साइमा वाजेद को ICONSIAM, बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 24वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन (IMHC) के दौरान प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य को आकार देने में उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व को मान्यता देता है।

● यह पुरस्कार थाईलैंड के मानसिक स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय, जिट्टावेजजसरी सोंगक्रोआ फाउंडेशन और सोमडेट चाओप्रया इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित IMHC 2025 के उद्घाटन दिवस पर प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैश्विक योगदान को सम्मानित करना है।

● साइमा वाजेद को न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर जागरूकता, ऑटिज्म वकालत, समावेशी शिक्षा और सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य में उनके अमूल्य प्रयासों के कारण इस सम्मान के लिए चुना गया था। उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया में मानसिक स्वास्थ्य नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

● फरवरी 2024 में, साइमा ने आधिकारिक तौर पर WHO-SEAR के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पदभार संभाला, जिससे वह बांग्लादेश से पहली व्यक्ति बन गईं और डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह (भारत) के बाद

WHO के छह वैश्विक क्षेत्रों में से एक का नेतृत्व करने वाली केवल दूसरी महिला बन गई।

Key Points:-

(i) बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद एक लाइसेंस प्राप्त स्कूल मनोवैज्ञानिक हैं। मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता समावेशन में उनके नेतृत्व के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उन्होंने 2015 में WHO-SEAR की क्षेत्रीय चैंपियन के रूप में कार्य किया और 2017 में उन्हें ऑटिज़्म के लिए WHO सद्भावना राजदूत नामित किया गया।

(ii) 2014 में, उन्हें WHO-SEAR के सार्वजनिक स्वास्थ्य में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। न्यूरोडेवलपमेंटल स्थितियों वाले बच्चों के लिए समावेशी नीतियों के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता ने क्षेत्रीय रूपरेखा को आकार दिया है।

(iii) WHO SEAR की स्थापना नवंबर 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। इस क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, DPR कोरिया और तिमोर-लेस्ते सहित 11 सदस्य देश शामिल हैं, जो नियमित रूप से प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर सहयोग करते हैं।

2. दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ़ फेम स्टार (क्लास ऑफ़ 2026) प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनकर इतिहास रच देंगी।



दीपिका पादुकोण को प्रतिष्ठित हॉलीवुड वॉक ऑफ़ फेम-क्लास 2026 के लिए चुना गया है, जिससे वह हॉलीवुड चैंबर ऑफ़ कॉमर्स द्वारा मोशन पिक्चर्स श्रेणी में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गईं।

• दीपिका पादुकोण का नाम आधिकारिक तौर पर 2 जुलाई, 2025 को घोषित किया गया, जिसमें माइली साइरस, टिमोथी चालमेट, डेमी मूर, एमिली ब्लंट और रामी मालेक जैसे वैश्विक आइकन शामिल थे। चयन के बाद 20 जून को वॉक ऑफ़ फेम चयन समिति द्वारा मतदान किया गया और 25 जून को अंतिम बोर्ड अनुसमर्थन किया गया।

• यह पुरस्कार दीपिका पादुकोण के वैश्विक सिनेमा में योगदान को मान्यता देता है—उनका करियर बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों, हॉलीवुड डेब्यू *Return of Xander Cage* (2017), और प्रतिष्ठित मंचों जैसे कान फिल्म फेस्टिवल और मेट गाला तक फैला है। उन्हें *TIME 100* (2018) में शामिल किया गया था और *Time100 Impact Award* (2022) से भी सम्मानित किया गया था।

• हॉलीवुड वॉक ऑफ़ फेम हॉलीवुड ब्लव्ड और वाइन स्ट्रीट के साथ 2,800 टेराज़ो-और-ब्रास सितारों से घिरा हुआ है। सम्मानित व्यक्तियों का चयन प्रशंसकों, एजेंटों या स्टूडियो द्वारा नामांकन के माध्यम से किया जाता है, एक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है, और चैंबर द्वारा अंतिम रूप दिया जाता

है। स्टार और समारोह की कुल लागत USD85,000 है।

Key Points:-

(i) पादुकोण का सितारा वैश्विक मनोरंजन मंच पर दक्षिण एशियाई प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वॉक ऑफ़ फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री और केवल तीसरी भारतीय (संगीतकारों और निर्देशकों के बाद) के रूप में, वह भारत के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव का प्रतीक हैं।

(ii) पुष्टि के बाद, सम्मानित व्यक्तियों को दो वर्षों के भीतर उद्घाटन समारोह में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें श्रद्धांजलियां और उत्सव भी शामिल होते हैं। पादुकोण का चयन भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देगा और बॉलीवुड की अंतरराष्ट्रीय पहचान को और सुदृढ़ करेगा।

(iii) पीटर रोथ (पूर्व वार्नर ब्रदर्स टीवी CEO) के नेतृत्व में वॉक ऑफ़ फेम समिति ने पादुकोण को उनकी सिनेमाई उपलब्धियों, सांस्कृतिक पहुंच और परोपकारी प्रभाव के आधार पर सैकड़ों वैश्विक नामांकितों में से चुना - जिससे हॉलीवुड के अभिजात वर्ग के बीच उनकी विरासत मजबूत हुई।

IMPORTANT DAYS

1. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा।



5 जुलाई 2025 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 103वें सहकारिता दिवस और संयुक्त राष्ट्र की मान्यता की 31वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसमें "एक बेहतर विश्व के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना" थीम के तहत समावेशी विकास में सहकारी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

● सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1844 में इंग्लैंड में रोशडेल पायनियर्स के साथ हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) ने 1923 में सहकारी दिवस मनाना शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 1992 में इसे मान्यता दी, जिसे पहली बार 1 जुलाई 1995 को मनाया गया - जिसे ICA की शताब्दी के साथ मेल खाने के लिए चुना गया था।

● 2025 का विषय - "एक बेहतर विश्व के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना" - लोकतांत्रिक, जन-केंद्रित समाधान पेश करके असमानता, पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक चुनौतियों से निपटने में सहकारी समितियों की भूमिका को रेखांकित करता है।

● 1995 से ICA और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA) द्वारा मनाए जाने वाले इस दिवस को सहकारिता संवर्धन एवं उन्नति समिति (COPAC) और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का समर्थन प्राप्त है।

Key Points:-

(i) दुनिया भर में सहकारी समितियाँ 1 बिलियन से ज्यादा सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कृषि, वित्त, आवास, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं। वे लोकतांत्रिक नियंत्रण और सामुदायिक सहभागिता के ज़रिए टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका को शक्ति प्रदान करती हैं।

(ii) जुलाई के पहले शनिवार को सहकारी समितियाँ जागरूकता अभियान, नीति संवाद, मेले और सोशल मीडिया कार्यक्रम (#CoopsDay) आयोजित करती

हैं। वे समुदायों में साझा स्वामित्व, एकजुटता और सहकारी मूल्यों को बढ़ावा देते हैं।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को मनाने से महत्वपूर्ण वर्षगांठों और सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन (नवंबर 2025) जैसे वैश्विक नीति निर्धारण कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारी समितियों की दृश्यता बढ़ जाती है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. अनंत टेक्नोलॉजीज 2028 तक भारत का पहला निजी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करेगी।



हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ATL) ने 4 टन के जियोस्टेशनरी (GEO) उपग्रह को लॉन्च करने के लिए IN-स्पेस से मंजूरी प्राप्त कर ली है, जो 100 Gbps तक की ब्रॉडबैंड क्षमता प्रदान करेगा, जो भारत की पहली निजी तौर पर संचालित उपग्रह इंटरनेट सेवा होगी, जो 2028 तक लाइव हो जाएगी।

● **IN-SPACE - भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र -** ने ATL की ब्रॉडबैंड परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जिससे यह लगभग 3,000 करोड़ रुपये (\$ 362 मिलियन) की प्रारंभिक वित्त पोषण प्रतिबद्धता के साथ पहला निजी भारतीय उपग्रह ऑपरेटर बन जाएगा, जिसे मांग के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

● एटीएल ने 35,000 किमी की ऊंचाई पर एक GEO उपग्रह (~4 टन, का-बैंड में काम करने वाला) लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो मल्टी-बीम, हाई-थ्रूपुट आर्किटेक्चर के माध्यम से 100 Gbps तक की गति से राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करेगा। स्टारलिनक जैसे LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) तारामंडलों के विपरीत, एक GEO उपग्रह पूरे उपमहाद्वीप को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

● जबकि स्टारलिनक, वनवेब और अमेज़ॉन कुइपर जैसे LEO सिस्टम कम विलंबता प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें सैकड़ों उपग्रहों की आवश्यकता होती है, ATL का एकल GEO उपग्रह व्यापक कवरेज प्रदान करेगा। हालाँकि GEO बीम में थोड़ी अधिक विलंबता होती है, लेकिन यह दृष्टिकोण पूंजी और परिचालन व्यय को काफी कम कर देता है।

Key Points:-

(i) अनंत टेक्नोलॉजीज वैश्विक खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में प्रवेश करती है। स्टारलिनक ने भारत में GMPCS लाइसेंस हासिल कर लिया है, जबकि भारती एयरटेल की भागीदारी विनियामक अनुमोदन के लिए लंबित है। अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में यूटेलसैट वनवेब और अमेज़ॉन कुइपर शामिल हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने उपग्रहों के माध्यम से स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए AST स्पेसमोबाइल के साथ मिलकर काम किया है।

(ii) यह पहल भारत के उपग्रह संचार में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करती है, डिजिटल समावेशन का विस्तार करती है, और ISRO जैसी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में निजी क्षेत्र के नेतृत्व को आगे बढ़ाती है।

ENVIRONMENT

1. अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय में नई फूलदार पौधे की प्रजाति 'बेगोनिया निशिओरम' की खोज की गई।



जून 2025 में, अरुणाचल प्रदेश (AR) के सेप्पा वन प्रभाग के वन अधिकारियों ने पूर्वी कामेंग जिले के पूर्वी हिमालयी जंगलों में बेगोनिया निशिओरम नामक एक नई उच्च-ऊँचाई वाले फूलदार पौधे की प्रजाति की खोज की। यह खोज भारत की वनस्पति विविधता में इज़ाफा करती है और इस क्षेत्र की पारिस्थितिक समृद्धि को उजागर करती है।

- इस पौधे की खोज जुलाई 2024 और जनवरी 2025 के बीच सेप्पा वन प्रभाग द्वारा किए गए "पूर्वी कामेंग जिले के दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों का दस्तावेज़ीकरण" नामक वन अभियान के दौरान की गई थी। इस अध्ययन का उद्देश्य इस दूरस्थ जैव विविधता हॉटस्पॉट से कम ज्ञात प्रजातियों की पहचान करना और उनका संरक्षण करना था।

- बेगोनिया निशिओरम एक छाया-प्रेमी प्रजाति है जो समुद्र तल से 1,500 से 3,000 मीटर की ऊँचाई पर नम, पहाड़ी ढलानों पर पनपती है। इसका निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग क्षेत्र के ठंडे, जंगली ऊँचे इलाकों में है।

Key Points:-

(i) यह प्रजाति अपने हल्के हरे रंग के डंठलों पर

लाल-किनारे वाले इंडुमेंटम (तराजू) की उपस्थिति के कारण दृष्टिगत रूप से अद्वितीय है, यह विशेषता एशिया भर में किसी अन्य बेगोनिया प्रजाति में नहीं पाई जाती है।

(ii) यह विशेषता वनस्पतिशास्त्रियों को इसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त 2,150 से अधिक बेगोनिया प्रजातियों से अलग करने में भी मदद करती है।

(iii) यह पौधा वर्तमान में पूर्वी कामेंग के भीतर केवल दो सुदूर वन स्थानों से ही जाना जाता है। इसका नाम, न्यिशियोरम, अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वदेशी समुदाय, न्यिशी जनजाति को श्रद्धांजलि देता है, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में उनके पारंपरिक प्रयासों को मान्यता देता है। इस खोज को औपचारिक रूप से वनस्पति विज्ञान पत्रिका नोवोन: ए जर्नल फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में प्रकाशित किया गया है।

Static GK

MoD	मंत्री: राजनाथ सिंह	मुख्यालय: नई दिल्ली
Naval Physical and Oceanographic Laboratory (NPOL)	निदेशक : डॉ. दुव्वुरी शेषगिरी	मुख्यालय : कोच्चि, केरल
Odisha	मुख्यमंत्री: मोहन चरण माझी	राज्यपाल: हरि बाबू कंभमपति
World Organisation for Animal Health (WOAH)	महानिदेशक (DG) : डॉ. इमैनुएल सौबेरन	मुख्यालय : पेरिस, फ्रांस
Spain	राष्ट्रपति : पेड्रो सांचेज़	राजधानी : मैड्रिड
NITI Aayog	CEO : बीवर सुब्रमण्यम	मुख्यालय: नई दिल्ली
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
Iran	राजधानी: तेहरान	राष्ट्रपति: मसूद पेजेशकियन
Gujarat	मुख्यमंत्री (CM) : भूपेन्द्र पटेल	राज्यपाल : आचार्य देवव्रत
ADB	अध्यक्ष:	मुख्यालय:

	मासातो कांडा	मंडालुयोंग शहर, फिलीपींस
SBI	अध्यक्ष: चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी	मुख्यालय: मुंबई
Microsoft	CEO : सत्य नडेला	अध्यक्ष: ब्रैडफोर्ड एल. स्मिथ